Government in respect of norms for distribution and release of Central plan assistance;

(b) if so, details of serious lacunae and inequities pointed out by Karnataka; and

(c) what are the corrective steps proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to norms few allocation of Central assistance. Suggestions on this subject have been received from Chief Ministers of several States including Karnataka, Central Assistance to non-Special Category States is formula based. The formula approved at the NDC meeting in December, 1991 takes into consideration their suggestions and gives due weightage to population, per capita income, tax effort, fiscal management, performance in relation to national objectives and special problems.

Declaration of some Districts in Uttar Pradesh as 'Zero-Industry Districts

51. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare some districts in Uttar Pradesh as 'Zero-Industry districts';

(b) if so, what are the names of the such districts; and

(c) what are the norms for declaring districts as 'zero-industry districts'?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) The following districts of Uttar Pradesh were decler-ed "no industry districts" in 1971:—Banda, Fatehpur, Hamirpur, Jalaun, Aunpur, Sultanpur, Kanpur Dehat, Chamoli, Pauri Garihwal, Tehri Garhwal, Uttar Kashi, Almora, Pithoragarh, Dehradun, National,

'No industry districts are those districts where no medium or large scale industry exists.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का पुनर्गठन किया जाना

52. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मार्च, 1991 के अन्त तक भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है; यदि हां, तो कितनी राशि का वित्तीय घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार ने इस भारी वित्तीय घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निगम के कार्यकरण का जिसमें उसके कारखानों की उत्पादकता, उनकी खरीद, विपणन, प्रशासनिक व्यवस्था और उनका व्यय तथा निगम को पुनर्गठित करना भी सम्मिलित है, व्यापक अध्ययन करने के लिए पनल नियुक्त करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और यदि हां, तो कब तक?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत: (क) जी हां। मार्च, 1991 के अन्त तक एन, टी सी को 2016.27 करोड़ रु. का संचित निवल घाटा हुआ।

(ख) एन टी सी मिलों में घाटों के लिए मुख्य कारण हैं, अप्रचलित मशीन, कम उत्पादकता, फालतू श्रमिक बल, घटिया काय व्यवस्था, कम क्षम तथा उपयोग, अपर्याप्त आधुनिकीकरण तथा कार्यशील पूंजी के लिए निधियों की कमी आदि।

(ग) और (घ) पैनल की कोई आवश्यकता नहीं है। एच टी सी ने